खाद्य प्रसंस्करण की 19 परियोजनाओं को मंजूरी

राज्य ब्यूरो, जागरण● लखनऊ: उप्र खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 के तहत 19 नई परियोजनाएं शुरू होंगी। राज्य स्तरीय एंपावर्ड समिति ने इन परियोजनाओं को अनुमोदित कर दिया है। वहीं प्रशिक्षण केंद्रों के आधुनिकीकरण के लिए भी सहमति दी गई है।

बुधवार को लोकभवन में कृषि उत्पादन आयुक्त दीपक कुमार की अध्यक्षता में हुई एंपावर्ड समिति की बैठक में परियोजनाओं के प्रस्ताव रखे गए थे। समिति ने सभी को लेटर आफ कंफर्ट (एलओसी) जारी किए जाने की स्वीकृति दी। तय हुआ कि संबंधित इकाई जब उत्पादन शुरू करेगी, तब नियमानुसार मंडी शुल्क, स्टांप ड्यूटी की प्रतिपूर्ति की योजना बनाई जाएगी। यह भी कहा गया कि अग्निशमन और प्रदूषण प्रमाणपत्र की समस्या के निदान के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को अप्रेजल समिति की बैठक में विशेष तौर पर आमंत्रित कर चर्चा की जाए।

समिति ने विभागीय 77 राजकीय सामुदायिक फल संरक्षण एवं प्रशिक्षण केंद्रों के उच्चीकरण के प्रस्ताव पर भी सहमति जताई। इन केंद्रों में प्रतिवर्ष लगभग एक हजार युवाओं को सर्टिफिकेट उपलब्ध कराया जाएगा।

अपर मुख्य सचिव उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण बीएल मीणा ने बताया कि 75 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाने पर मिलने वाली सब्सिडी का 100 से अधिक उद्यमियों ने लाभ लिया है।

फ्रांस में रोड शो करेगा इन्वेस्ट यूपी

राज्य में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए इन्वेस्ट यूपी ने फ्रांस में रोड शो करने की रणनीति तय की है। इस संदर्भ में बुधवार को इंडो-फ्रेंच चैंबर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री (आइएफसीसीआइ) के प्रतिनिधियों के साथ हुई आनलाइन बैठक में रोड शो की तैयारियों पर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए इन्वेस्ट यूपी के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी शशांक चौधरी ने राज्य की लाजिस्टिक्स क्षमता, एक्सप्रेसवे और अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों की उपलब्धता की जानकारी फ्रांस के प्रतिनिधियों को दी।